THE VICE CHAIRMAN (SHRI SAWAISINGH SISODIA): Calling Attention.

CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

Low Price of Paddy suggested by Agriculturtra Prices Commission Causing Hardship and Misery to Farmers

SHRI KALPNATH RAI (Uttar Pradesh): Sir, I beg ta call the attention of the Minister of Agriculture to the 1)W price of paddy at Rs. 1001 - per quintal suggested by the Agricultural Prices Commission which is bound to cause great hardship and misery to the farmers who have already been hard hit due to the increase in prises of fertilizer and diesel and th< steps taken by Government to remedy the situation.

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND RURAL RECONSTRUCTION (RAO BIRENDRA SINGH): Sir, as the He nourable Members are aware Agricu tural Prices' Commission is a I ecosmmendatory body. While making recommendations on price policy it is expected to keep in view: —

(i) The need to provide incentive to the producer for adopting improved t-chnology and for developing : production pattern broadly in t ie light of national requirements;

(ii) The need to ensure rational utilisation *oi* land, water and other production resources;

(iii) The likely effect of the price policy on the rest of the economy, parti :ularly on the cost of living, level of wages, industrial cost structure, etc.

2. In May, 1980, the Commission had submitted its Report on price poUcy for kharif cereals for 1980-81 season. In this Report, the Commission had recoTimended that the prices of naddy anc other kharif cereals might be retaned at Rs. 95/- per | quintal. Sometime later in June, 1980, Government of India made an announcement about the increase in the prices of fertilizers and whila doing so, the A.P.C. was asked to rework its price recommendations. This was necessary because at the time of announcing increase in the prices of fertilizer and diesel oil Government had decided that the farmers would be compensated for increases in their cost. It was envisaged by Government that appropriate increases in procurement/support prices mav be affected from the kharif 1980-81 season itself. Accordingly, the Agricultural prices Commission submitted a supplementary report on price policy for kharif cereals for 1980-81. After taking into account the likely effect of the rise in the prices of fertilizer and diesel and the quantities and values of diesel and fertilizers used by cultivators on different kharif crops, the Commission recommended a procurement price °f Rs. 100/- per quintal for paddy and Rs.97.50 for the coarse kharif cereals viz. jowar, bajra, maize and ragi. In order to hold consultations with the State Governments on the price policy for kharif cereals a Conference of State Chief Ministers was convened by us on 27th July, 1980 in New Delhi. Government would fix the prices of kharif cereals after duly considering the views on the subject expressed by the State Governments. Thus the procurement prices for paddy and coarse cereals for 1980-81 are still to be fixed.

3. Honourable Members have stated that the farmers of India are facing hardship due to increase i» the prices of fertilizer and diesel. I share the Members' concern. The increase in fertilizer prices has been made undercompelling circumstances. It is necessary to note that the entire potassic fertilizer used in this country is imported. In January, 1979, the international price of this fertilizer was 63 dollars per tonne and by June, 1980 it had risen to nearly 120 dollars per tonne. In the same

[Rao Birendra Singh]

way, international price of DAP has risen from 160 dollars per tonne in January, 1979 tO 260 dollars in December, 1979. The ocean freights have also nearly doubled in the last two years. Not only this the prices of imported raw materials like sulphur, phospheric acid and roac phosphate have also witnessed a steep escalation. These developments have forced the Government to decide for a rise in fertilizer prices. However, I wish to clarify that despite these price increases the Central Exchequer would still be bearing a sizeable financial burden on account of fertilizers. In fact, the total burden which the Central Exchequer would bear in 1980-81 would be Rs. 585 crores on account of fertilizers as against Rs. 562 crores which was the expenditure on fertilizer subsidy in 1979-80. This is because even after ttie price rise of June, 1980, the imported Urea would carry a Government subsidy of more than Rs. 700 per tonne and the imported MOP would carry subsidy of Rs. 550 per tonne.

4. We have also taken a major decision under which both the imported fertilizers and domestically produced fertilizers will be supplied to farmers at fixed prices at all block headquarters even where they are not connected by any rail head nearby. This measure would ensure availability of fertilizers to the interior villages. The provision of subsidy to all small and marginal cultivators in the areas affected by drought during the previous year would also be continued in the current year. In this way, Government is trying to ensure that the hardship to cultivators arising from unavoidable increase in fertilizer price is minimised.

श्री कल्पनाथ राय : आदरणीय कृषि मंत्री जी ने जो बातें कही हैं, हम उससे भी सहमत हैं। लेकिन 12 मार्च, 1980 को कृषि मंत्री महोदय ने यह घोषणा की थी कि नान-एग्रीकल्चरल सैक्टर में जो गुडस हैं उनकी प्राइसेज के अनुकूल ही एग्रीकल्चरल गुडस की प्राइसेज डिटर्रामन होंगे और एग्रीकल्चरल प्राइसेज कमीशन को नये टर्म्स आफ रेफरेंस दिये गये माननीय मंत्री जी की तरफ से और कबिनेट ने इसको पास किया।

तो मेरा यह कहना है कि जिस समय 12 मार्च, 1980 को आपने यह घोषणा की और कबिनेट ने निर्णय किया, उस दिन से आज तक एग्रीकल्चरल कमोडिटीज के प्राइसेज का इंडैक्स कितना बढ़ा है और जो फैक्ट्रीज में मनुफैक्चर्ड गुड्स हैं, जिनका इस्तेमाल किसान करते हैं, उनका प्राइस कितना बढ़ा है? क्या एग्रीकल्चरल प्राइसेज कमीशन ने आपकी टर्म्स आफ रेफरेंस के अनुकूल खेत में पैदा होने वाली चीजों और कारखाने में पैदा होने वाली चीजों के प्राइसेज में पैरिटी स्थापित करने की कोशिश की है, या नहीं? यह मेरा पहला सवाल है।

दूसरे आज खेती करने वाले किसानों की हालत जितनी खराब है, उतनी मैं समझता हूं कि इसके पहले कभी नहीं थी। जितना भी सामान किसान आज बाजार से खरीदता है, चाहे सिमेंट खरीदता हो—दूसरी बात मैं आपसे पूछूंगा कि जब आपने यह घोषणा की कि नान-एग्रीकल्चरल सैक्टर की प्राइसेज के अनुकल ही एग्रीकल्चरल प्राइसेज डिटरमिन होंगीं तो क्या आपने कुछ सामान की लिस्ट बनाई कि फलां-फलां सामान दस, पंद्रह, बीस आर्टिकल्स जो कारखानों में बन रहे हैं, इनके दाम क्या हैं और जो एग्रीकल्चर में पैदा होते हैं, उनके दाम क्या हैं? सरकार की वज्ञानिक नीति के न होने के परिणामस्वरूप आज स्थिति बड़ी ही नाजुक हो गई है। आज से तीन साल पहले जब जनता सरकार, लोक दल की हुकूमत थी, उस समय छः रुपये गन्ने का दाम था, आज चीनी आठ रुपये किलो बिक रही है यानी, किसानों ने गन्ना पैदा किया और छः रुपये क्विंटल के हिसाब से जनता सरकार

के राज में गन्ना बिका और चीनी 8 रु० किलो के हिसाब से । जब किसान ने आलू पैदा किया तो 12 रु० क्विंटल के दाम से उसका आलू बिका और जब उसने कोल्ड स्टोरेज से आलू खरीदा तो 250 रु० क्विंटल के हिसाब से खरीदा । जब उसने प्याज पैदा किया तो 8 आने किलो० बेचा और बाजार में वह आलू 5 रु० किलो बिकने लगा । यह सरकार जब तक किसानों के खेत में पैदा होने वाली चीजों के दाम वैज्ञानिक ढंग से निर्धारित नहीं करेगी तब तक किसानों की हालत बद से बदतर होती जाएगी । आदरणीय कृषि मंत्री एक किसान हैं और उनसे ऊपर देश के किसानों को बड़ा भरोसा है और उपसभाध्यक्ष महोदय, आज ही जो चीफ मिनिस्टर्स कांफरेंस हुई है

It is reported: "All the States want paddy prices at Rs. 130 per quintal"

सारे मुख्य मंत्रियों ने यह कहा है कि किसी भी कीमत पर 130 रु०, 140रु० से कम दाम निर्धारित न हों । जो राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं उन्होंने भी कहा है कि 130 रु० से कम दाम निर्धारित किया तो इसके बड़े ही खराब परिणाम होंगे ।

उपसभाध्यक्ष महोदय, मुझे मंत्री जी के सामने दूसरा निवेदन यह करना है कि हरियाणा में अगर एक किसान के पास 10 एकड़ का खेत है और उसको बेच दे तो 15,000 रु० प्रति एकड़ के हिसाब से बेचेगा तो 10 एकड़ मार्जिनल फार्मर को उसकी कीमत डेढ़ लाख रुपए मिलेगी और अगर वह दिल्ली में किसी बैंक में वह रकम जमा कर दे उसे 20,000 रु० सालाना सूद मिलेगा, फिक्सड डिपाजिट में । इस प्रकार पांच आदमियों का परिवार 20,000 रु० में बिना कोई काम किए दिल्ली में अपना जीवन चला सकता है बजाए इसके कि 10 एकड़ की जमीन में दिन-रात मेहनत मजदूरी करता रहे और फिर कहीं बाढ़ आ जाए तो सारी फसल नष्ट हो जाए, कोई सूखा हो जाए उसकी तो फसल मारी जाए और उसको अपनी जिंदगी कर्ज पर बितानी होगी । उपसभाध्यक्ष महोदय, हिन्दुस्तान के 7 लाख गांवों में बसे जो किसान हैं उनमें जितने कर्जदार हैं उनका अगर सर्वे यह सरकार कराए तो पता चलेगा कि इतना कर्ज पूरे देश के अंदर कहीं नहीं है । अगर कोई कारखाना घाटे में चला जाए तो इंडस्ट्री मिनिस्ट्री का ब्यूरो आफ कास्ट कायम किया है और अगर कोई घाटा हुआ है तो सरकार उसको सबसिडी देगी, लेकिन अगर बाढ़, अतिवृष्टि और अनावृष्टि के कारण किसान, जो कि देश की रीढ़ हैं, उनकी फसल नष्ट होती है तो उसकी गारन्टी सरकार की तरफ से कोई नहीं होती । आप जानते हैं आदरणीय उपसभाध्यक्ष महोदय, कि जब हमारे देश में गेहूं की कमी रहती थी और हमारी सरकार अमरीका से गेहूं खरीदती थी, तो 1974 में 178 रु० प्रति क्विंटल के हिसाब से हमें अमरीकी पूंजीपतियों से, व्यापारियों से गेहूं खरीदना पड़ा और इस तरह हमने अपने डोमेस्टिक नीड को मीट आऊट किया और 711 करोड़ रु० हमने अमरीका को दिया । जब किसान ने गेहूं पैदा करना शुरू--किया और हमने बफर स्टाक भी रख लिया तो आज गांव में रहने वाले किसान की हालत इतनी खराब हो गई क्योंकि सीमेंट का दाम पिछले छः महीने में दूना-तिगुना बढ़ गया, लोहे का दाम तिगुना बढ़ गया, कपड़े का दाम दूना तिगुना हो गया । ये जो कारखाने में बनने वाली चीजें हैं उनके दाम कभी घटते नहीं हैं, लगातार बढ़ते जा रहे हैं; कभी घटे नहीं । लेकिन जो चीजें किसान के खेत में पैदा होती हैं

[श्री कल्पनाथ राय]

जब पैदा हुई तो मिट्टी के दाम, जब बाजार में गई तो सोने के दाम हो गए। चाहे आलू हो, चाहे प्याज हो, चाहे गेहूं हो, सब में यही हालत है। उपसभाध्यक्ष महोदय, मेरे एक मित्र ने कहा साहब, इस तरह की बात आप उठाते हैं इससे तो एक कुलक लाबी की बात आती है। मैं आपके सामने निवेदन करना चाहता हूं कि 1951 में हिन्दुस्तान में खेती करने वाले किसानों की संख्या 50 प्रतिशत थी, 1974 में....

उपसभाध्यक्ष (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : आप मेहरबानी करके सीधा प्रश्न पूछिए।

श्री कल्पनाथ राय : ... खेती करने वाले किसानों की संख्या 50 प्रतिशत से घट कर 43 प्रतिशत हो गई और 1980 में खेती करने वाले किसानों की संख्या घटकर 40 प्रतिशत हो गई। तो खेती करने वाले किसान खेती को छोड़ कर भाग रहे हैं और दो एकड़, तीन एकड़, चार एकड़ और पांच एकड़ में खेती करने वाले अपने खेतों को बेच कर, शहर में जाकर फल की और पान की दुकान लगा कर बेचना पसन्द कर रहे हैं लेकिन खेती करना...

उपसभाध्यक्ष (श्री सवाई सिंह सिसोदीया) : आप सुझावों पर आएं।

श्री कल्पनाथ राय : सबसे तबाह जो किसान है, दो-तीन-चार एकड़ का किसान इतना तबाह है उपसभाध्यक्ष महोदय, कि वह अपने खेत को गिरवी दे रहा है क्योंकि उसके खेत में जब कोई पैदावार होती है तो अपनी बेटी की शादी या किसी और खर्च को मीट आऊट करने के लिए अपनी एग्रिकलचरल कमोडिटी बेच देता है। और सस्ते दाम पर बेचता है और इस के बाद उसे मंहगे दाम पर खरीदना पड़ता है। उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं कृषि मंत्री राव बीरेन्द्र सिंह से और उन के माध्यम से प्रधान मंत्री से भी निवेदन करना चाहता हूं कि वे किसान की ओर, जो हिन्दुस्तान की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, विशेष ध्यान दें। किसी भी डवेलपिंग कन्ट्री में कृषि ही मुल्क के डेवलपमेंट का बेस बनती है। एग्रो-बेस्ड इंडस्ट्रीज का आप सपना देखते हैं। हम आप से निवेदन करना चाहते हैं कि देश के किसानों की स्थिति को सुधारने के लिए आप एग्रीकल्चरल प्राइसेज कमीशन के जो केबिनेट ने और आप ने टर्म्स आफ रिफरेंस निर्धारित किये हैं उन टर्म्स आफ रिफरेंस के अनुकूल ही आप यह तय करें कि हिन्दुस्तान के गांवों में किसानों का क्या कास्ट आफ प्रोडक्शन होता है और कितनी पैदावार होती है। आप ने वादा किया था कि हम रेमूनरेटिव प्राइस देंगे, हम प्रोफिट देंगे जब कि आप के ही मुख्य मंत्रियों ने कहा है कि कास्ट आफ प्रोडक्शन पैडी का फील्ड पर पन्तनगर के अन्दर या केन्द्रीय विश्वविद्यालय के अन्दर 114 या 125 रुपए आता है। तो अगर रेमूनरेटिव प्राइस देंगे तो वह 130 होगा, प्रोफिट दें तो 140 होगा। आप ने ही, केन्द्रीय सरकार ने ही निर्णय किया कि हम रेमूनरेटिव प्राइस देंगे, प्रोफिट देंगे। तो कम से कम 125 रुपए प्रति क्विंटल वर्तमान परिस्थिति का दाम सरकार द्वारा निर्धारित किया जाना चाहिए ताकि किसान जान बचा सकें और गांव को छोड़ कर भाग न जायं, दिवालिया न हो जायें।

अन्तिम निवेदन, उपसभाध्यक्ष महोदय, यह है कि सरकार व्हीट पर 33 प्रतिशत सबसिडी कन्ज्यूमर्स को देती है और पैडी पर 26 परसेंट सबसिडी देती है। तो क्यों नहीं किसानों को कम से कम 15 फीसदी सबसिडी देती ताकि फार्मर्स, मार्जिनल फार्मर्स, देश के किसान अपने जीवन को

बचा सकें और देश की अर्थ व्यवस्था को मजबूत बनाने में अपना अहम् रोल अदा कर सकें।

श्री पी० राममूर्ति (तमिलनाडु) : सवाल ही नहीं पूछा।

श्री कल्पनाथ राय : आप अंग्रेजी में पढ़ते हैं।

राव बीरेन्द्र सिंह : वाइस चेयरमैन साहब, श्री कल्पनाथ राय जी ने बहुत सुन्दर शब्दों में हाउस का ध्यान किसान की हालत की तरफ दिलाया। मैं करीब-करीब सब बातों में उन के साथ सहमत हूं। लेकिन जब कीमत का सवाल आता है तो हमें दो तरफ देखना पड़ता है।

श्री सदा शिव बागाईतकर (महाराष्ट्र) : तो सहमत किस से हैं ?

उपसभाध्यक्ष (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : बागाईतकर जी, पूरी बात सुनिये।

राव बीरेन्द्र सिंह : कीमत मुकर्रर करते वक्त हमें कन्ज्यूमर्स की तरफ भी देखना पड़ता है। हिन्दुस्तान में बहुत भारी संख्या ऐसे लोगों की है जो खुद तो खेती नहीं करते, अनाज पैदा नहीं करते, मजदूरी करते हैं, बगैर जमीन वाले लोग हैं। उन लोगों के लिये अनाज सस्ता मुहैया करना सरकार का फर्ज है। लेकिन इस के साथ हो जितना भी हम से हो सकता है किसान को रम्यूनरेटिव कीमत दिलाने की तरफ हमारी तवज्जह रहती है और मुख्तलिफ कदम इस सिलसिले में हमने पीछे उठाये हैं।

श्री राय ने कहा कि एग्रीकल्चरल प्राइसेज कमीशन के टर्म्स आफ रेफरेंस में हम ने तबदीली की थी। उस का मकसद किसी हद तक एग्रीकल्चरल और नान-एग्रीकल्चरल सेक्टर्स में टर्म्स आफ ट्रेड का जायजा ले कर जहां तक हो सके पैरिटी लाने का जरूर था, लेकिन पूरे तौर पर इन दोनों सेक्टर्स में पैरिटी लाना असम्भव है, बहुत ही मुश्किल काम है। बहुत सी चीजों का भाव बहुत बढ़ गया है, बाजार के अन्दर मंहगी मिल रही है। फिर सवाल यह होता है कि उन का कास्ट आफ प्रोडक्शन क्या है और कितने कारखानों को प्राफिट मिलता है और किस तरह से वे अपना कास्ट आफ प्रोडक्शन बढ़ा चढ़ा कर दिखाते हैं। उन की कीमतें भी किसी आधार पर तय जरूर होती हैं, लेकिन वे आधार गलत होते हैं मसलन किसान यह नहीं दिखा सकता कि कितने एग्जीक्यूटिव बाहर गये, कैसे-कैसे होटलों में ठहरे, कितना एडवर्टाइजमेंट्स के ऊपर उन का खर्चा हुआ। कम्पनीज के मामले में, फैक्ट्रीज के मामले में यह सारा खर्चा कास्ट आफ प्रोडक्शन में शामिल हो जाता है। तो इन सारी बातों को सरकार जानती जरूर है। हमारा इस तरफ ध्यान है। किसान को मुनासिब कीमत दिलाने के लिये ही हम ने यह तब्दीली टर्म्स आफ रिफरेंस में की थी। पहली बात और साथ ही एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन को यह अख्तियार भी दिये थे कि युनिवर्सिटीज और दूसरे इंस्टीट्यूशन्स जो हैं या जो एजेंसीज हैं खाली उनकी इकट्ठा की हुई फीगर्स पर और उन के डाटा पर ही वह निर्भर न रहें बल्कि अपने आप भी रिसर्च कर के देखें कि ऐसे हालात में कास्ट आफ प्रोडक्शन किसान की क्या है और कितनी कीमत देने से उस को रिम्यूनरेटिव प्राइस मिलगी। तो हम ने यह भी एक नया अख्तियार दिया है जब टर्म्स आफ रिफरेंस उन का तबदील किया। एग्रीकल्चर प्राइसेज कमीशन तो एक्सपोर्टस का बाडी हैं।

[राव बीरेन्द्र सिंह]

सारी चीजों के लिये वह सम्पूर्ण डाटा इकट्ठा कर के देखता है, कोई आधार बताता है, आर्गूमेंट्स देता है और फिर रिपोर्ट देता है और इन सारी बातों पर कैबिनेट विचार कर के कीमत तय करती है और अब की बार तो हम ने पार्लियामेंट की सेलेक्ट कमेटी जो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री की है उस से भी 26 तारीख को बात की, उस के आनरेबिल मेम्बर्स से और फिर 27 तारीख को चीफ मिनिस्टर्स की राय ली और वह सारी चीजें कैबिनेट की रिपोर्ट कर के जहां तक हो सकेगा मुनासिब फैसला कराने की सरकार से कोशिश करेंगे। मैं यह नहीं कह सकता कि जैसा कि श्री राय ने कहा कि 125 रुपया होना चाहिये कुछ चीफ मिनिस्टर्स ने 140 की मांग की, किसी ने 130 की मांग की और कुछ ऐसे थे कि जो कहते थे कि भाव नहीं बढ़ने चाहियें। यह हालात पर मुनहसिर है कि किस स्टेट में वहां की ज्यादा आबादी क्या चाहती है। वह आबादी खाने वालों की है या ज्यादा उगाने वालो की है और उस के मुताबिक ही वह अपनी राय देते हैं। लेकिन सरकार को इस सारे मामले में पूरी तवज्जह दे कर, पूरा ध्यान दे कर विचार करना है और वह जल्दी ही इस बात का निर्णय करेगी और मैं यकीन दिलाना चाहता हूं कि किसानों की बेहतरी और बेहबूदी हर वक्त हमारे ख्याल में है।

शुगर का जिक्र किया श्री कल्पनाथ राय जी ने कि वह मंहगी हो रही हैं, लेकिन हम ने उस के भाव को कंट्रोल करने में कोई कसर नही छोडी। अगर कोई और तरीका उन की निगाह में हो या कोई आनरेबिल मेम्बर्स की निगाह में हो तो वह तरीका या कोई और तरकीब वह हमें बतलायें कि वह कहां छिपी हुई है, कैसे छिपी हुई है, क्यों यह कीमत बढ रहीं है और व्यापारियों के ऊपर कैसे और काबू पाया जा सकता है, जो दिन रात कमाई की फिक्र में रहते हैं। जो सुझाव आयेंगे उन पर और दूसरी चीजों पर भी हम पूरा पूरा ध्यान देंगे और उन से फायदा हासिल करने की कोशिश करेंगे ताकि शुगर की कीमतें काबू में आ सकें।

श्री सुन्दर सिंह भंडारी (उत्तर प्रदेश) : एफ० सी० आई० छिपा रहा है।

राव बीरेन्द्र सिंह : वह तो एक-एक बैग का हिसाब देता है। आप यह भी कह देंगे कि सरकार छिपा रही है। यह मेहरबानी आप की है कि अभी आप एफ० सी०आई० तक ही पहुंचे हैं।

श्री सुन्दर सिंह भंडारी : उस के बाद आप का नम्बर आयगा।

राव बीरेन्द्र सिंह : अब की बार शुगर केन की कीमत किसानों को काफी अच्छी मिली है, पीछे भी मिलेगी। चौधरी चरण सिंह के और जनता राज के वक्त में जब का कि आप ने जिक्र किया यह ठीक है कि किसानों ने बहुत कम पैदावार शुगर केन की क्योंकि उन को भाव पूरा नहीं मिला था। 6 रुपये गन्ना बिका और मुझे मालूम है कि तीन और साढे तीन रुपये क्विंटल का दाम भी उन को नहीं मिला और उन को अपने खेतों में आग लगानी पड़ी और इस वजह से उन्होंने गन्ना कम बोने। लेकिन इस बार 25 रुपये 26 रुपये तक क्विंटल के हिसाब से किसान को मिलेगा और मैंने जानबूझ कर कोई रोक लगाने की कोशिश नहीं की क्योंकि मैं चाहता था कि किसान को पिछले नुकसान का जितना भी मुआवजा मिल जाये, जितनी कमी पूरी हो जाये अच्छा है। ताकि वह आगे गन्ना बोये। भगवान की दया से गन्ने की काश्त अच्छी हुई है। भगवान खुश नजर आते हैं

बारिश भी अच्छी हुई है और उम्मीद है कि शुगर की यह कमी दूर होगी और आलू का भी बुरा हाल पीछे रहा, लेकिन जो बात हमारे दोस्त कल्पनाथ जी ने कही कि आलू सड़ता रहा वह पहले की बात है। वह वक्त गुजर गया। अब की बार आलू की फसल आ चुकी है लेकिन आप को जानकर खुशी होगी कि मार्च अप्रैल के बाद आलू की क़ीमतें बढ़ती जा रही हैं और किसान को काफी पैसा मिल रहा है। फरुखाबाद में, बंगलौर में, पटना में, सभी मंडियों में जहां आलू ज्यादा पैदा होता है हिमाचल में कोशिश इस बात की है कि आलू की कीमत इतनी कम न हो कि जिस से किसान को नुकसान हो। जिस वक्त आलू की कीमत कम होनी शुरू होगी फारेन सरकार कोई न कोई ऐसा तरीका निकालेगी खरीद का कि किसानों को नुकसान न होने पाये। प्याज के मामले में आपने देख ही लिया। ज्योंहि प्याज की कीमत गिरने लगी, 20-25 रुपये महाराष्ट्र और गुजरात में प्याज बिकने लगी और खरीद नहीं हुई तो हमने फौरन 'नेफेड' को कहा, एक सरकारी कोआपरेटिव एजेंसी कि वह प्याज की खरीद शुरू करे। दो लाख सात हजार टन प्याज फौरन खरीद ली गई। थोड़े दिनों के अन्दर ही प्याज के भाव ठहर गये और किसान नुकसान से बच गये। अब प्याज के भाव देश में ऐसे नहीं हैं जिससे परेशानी हो और अब हमें एक्सपोर्ट के लिये गुंजाइश भी नजर आती है। इसमें सरकार को ज्यादा सबसिडी भी नहीं देनी पड़ेगी। किसानों के लिये, प्याज की खरीद पर नफेड को साढ़े छः करोड़ दिये नुकसान के। मतलब यह है कि सरकार फारेन कोशिश करती है कि किसी तरीके से पैसे की तरफ न देख कर किसानों को नुकसान से बचाये। इस मामले में उनको फिकर नहीं होनी चाहिये।

माननीय कल्पनाथ राय जी ने सही कहा है कि किसानों को रिटर्न बहुत कम मिलती है। यह भी सही है क्योंकि मैं तो जानता हूं इस चीज को कि बहुत से लोग जिनके पास थोड़ी खेती है, कम जमीन है वह उसको छोड़ कर दूसरे धंधे में लग जाते हैं और देश के दूसरे इलाकों में जहां सिंचाई और नहर आदि का प्रबन्ध नहीं है जैसे राजस्थान है वहां से छोड़-छोड़ कर शहरों में आकर मजदूरी करते हैं, ईंट और गारा का काम करते हैं इसलिये कि उनका गुजारा नहीं होता है। बहुत सी जगहों पर किसानों की बुरी हालत है। ऐसे छोटे किसानों की मदद के लिये हमने डी० पी० ए० पी० और और एस० एफ० डी० ए० बना रखे हैं खरीद की फैसिलिटी है। उनको सबसिडी भी मिलती है। हर तरीके से हम उनकी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। जो लोग खेती करते हैं वे खेती का धंधा छोड़ कर न भागें, उनके लिये रेम्यूनरेशन है, उनको इनसेन्टिव सरकार की तरफ से मिलता है।

माननीय कल्पनाथ राय जी ने जो सुझाव दिया है वह बहुत अच्छा है। मैं इसको जरूर आगे चलाऊंगा। उन्होंने कहा है कि किसान कितना कर्जे में दबा हुआ है हिन्दुस्तान के अन्दर इसका सही सर्वे शायद अभी तक नहीं हुआ है। कई बार वे अपना कर्जा अदा नहीं कर सकते। दो सौ, ढ़ाई सौ रुपये तकावी लोन लेते हैं उसके लिये भी शायद वह रिश्वत देते हैं दलालों को। वह भी वे किसान पूरा नहीं कर सकते। बाढ़ आती है, सूखा पड़ता है तब जबर्दस्त मांग होती है कि पोस्टपोनमेंट हो। अगर दो सौ, ढ़ाई सौ रुपये का शोर्ट टर्म लोन किसान लौटा नहीं सकता सरकारी खजाने में, ज्यादा फसल होने के बाद, अगली फसल उठाने के बाद तो

[राव बीरेन्द्र सिंह]

अंदाजा यह होता है कि किसानों की हालत वाकई अच्छी नहीं है । सर्वे कराना जरूरी है यह पता करने के लिये कि कितना टोटल इनडेटनैंस किसानों का है, हिन्दुस्तान के मुखतलिफ हिस्सों में मुखतलिफ सूबों में कितना कुछ एरियर में है, रिकवरी नहीं कर पाये हैं या वे नहीं दे पाये हैं, कितना स्टेट गवर्नमेंट से रेम्युन रेट किया गया है, कितनी बार पोस्टपोनमेंट हुआ है । जब इन सब चीजों का सही पता लगेगा तब ही अंदाजा लग सकता है कि किसानों की हालत क्या है और उनको उठाने के लिये सरकार को क्या करना है । वरना आमतौर से मोटी सी बात कह दी जाती है कि किसान रिच हो गया । उसके पास पैसा है । वह ऐसा चंद एक किसानों को देख कर कहते हैं जो शायद एक दो परसेंट भी नहीं होंगे हिन्दुस्तान के अन्दर और शायद उनका दूसरा धंधा होता है, किसी का बिजनेस होता है । जैसा आपने फर्माया कि जो किसान खेती करता है वह अपनी जमीन बेच कर पैसा कमाता है । उस की वजह से थोड़ा पैसा उसके पास हो जाता है । ऐसे लोगों को जो अपनी जमीन बेच जाए या किसी दूसरे धंधे में पैसा लगा दें उनको देख कर लोग समझते हैं कि यह रिच किसान है । जबकि असल खेती करने वाला किसान ऐसा नहीं है । मैं समझता हूं मैंने कल्पनाथ राय जी की सारी बातों का जवाब दे दिया है ।

श्री कल्पनाथ राय : सबसिडी के बारे में बताएइ ।

राव बीरेन्द्र सिंह : आपने सबसिडी की बात कही है । कल पंजाब के चीफ मिनिस्टर सरदार दरबारा सिंह और हरियाणा के चीफ मिनिस्टर चौधरी भजन लाल जी ने भी इस चीज को उठाया था । यह सोचने की बात है कि किस हद तक हम इसमें कुछ कर सकते हैं । आपने कहा है कि गेहूं को जब हम तकसीम करते हैं, इशू करते हैं तो 33 रु० क्विंटल की सबसिडी देते हैं । चावल को इशू करने के लिए कोई 26 रु० क्विंटल सरकार नुकसान भोगती है । कल चीफ मिनिस्टर्स ने यही कहा था कि कंज्यूमर को खाने के लिए सरकार सबसीडी देती है । गेहूं के ऊपर 33 रु० और चावल के ऊपर 26 रु० क्विंटल देती है । उनका कहना था कि चावल के ऊपर कुछ इशू प्राइस बढ़ा दी जाये और जितना खाने के नाम पर दिया जाता है उससे आधा भी सरकारी खजाने से किसानों को दे दिया जाय तो अच्छा रहेगा । ए० पी० सी० ने 100 रु० की रिकमेंडेशन की है । आप लोगों ने भी सवाल उठाया है और दूसरे लोगों ने भी उठाया है । ए० पी० सी० ने बताया है कि पैडी को पैदा करने का खर्चा 92 रु० आता है ।

श्री हरकिशन सिंह सुरजीत (पंजाब) : यह पुराना हिसाब होगा ।

राव बीरेन्द्र सिंह : यह पुराना हिसाब है या नया है, यह तो पता नहीं, लेकिन उसने 100 रु० क़ीमत रिकमेंड की है । यही सवाल कल भी उठाया गया था जो आज श्री राय ने हाउस में उठाया है । इन बातों में वजन है और जैसा फरमाया गया है कि अगर खाने के लिए 26 रु० क्विंटल के हिसाब से सबसीडी मिलती है तो कम से कम किसानों को आधा यानी 13 रु० दे दो । ये सारी चीजें सरकार के ध्यान में हैं और हम सोच रहे हैं कि इसमें क्या कर सकते हैं । इसका फैसला जल्दी हो कैबिनेट में होगा और आपको मालूम हो जाएगा ।

श्री शिव चन्द्र झा (बिहार) : उपसभाध्यक्ष महोदय, अभी मंत्री महोदय ने इस

बात को कबूल किया है कि हमारे देश के ज्यादातर किसान कर्जे से लदे हुए हैं और धान बेचने वाले किसान बहुत कम हैं उन्होंने यह भी कहा कि हमारे देश में जो लोग कर्ज से लदे हुए हैं उनका परसेन्टेज कितना है, उसका हम सर्वे करा रहे हैं। शायद मंत्री महोदय को मालूम होगा कि इस बारे में पहले से ही दो कमीशन बैठ चुके हैं। एक एग्रीकल्चर लेबर इन्क्वायरी कमेटी बैठी थी। अब तक दो कमीशन इस बारे में बैठ चुके हैं। उन दोनों ने एग्रीकल्चर इंडेटनैस का एक नक्शा देश के सामने रखा था। उसके बाद से हमारे देश में किसानों की हालत में कोई विशेष सुधार नहीं हुआ है, बल्कि उनकी कर्जदारी और बढ़ी है। इसलिये मैं यह साफ तौर पर जानना चाहता हूं कि हमारे देश में किसानों की जो कर्जदारी बढ़ी है और आप जानते हैं कि हमारे देश में छोटे किसान धान नहीं बेच पाते हैं, इसलिये क्या आप कोई दूसरा एग्रीकल्चर लेबर इन्क्वायरी कमीशन बैठाने जा रहे हैं और क्या आप इस बात का भी पता लगायेंगे कि हमारे देश में कितने किसान ऐसे हैं जो अभी भी कर्ज से लदे हुए हैं?

दूसरा सवाल मेरा यह है कि पिछले सालों में फूड ग्रेन्स का जो प्रोडक्शन हुआ है और विज ए विज जो कैश क्राप्स हैं, उनकी वजह से क्या हमारे देश में ग्रेन्स की खेती कम नहीं हो गई है क्योंकि कैश क्राप्स में तो उसी वक्त पैसा मिल जाता है। आप साफ बतायें कि कितना परसेन्ट ग्रेन्स की खेती में कमी आई है और कितना परसेन्ट कैश क्राप्स में बढोत्तरी हुई है?

तीसरा सवाल मेरा यह है कि आपने यह कबूल किया है कि हमारे देश में किसानों की कर्जदारी बढ़ी है और किसानों की फसलें भी कई बार नष्ट हो जाती हैं। इसलिये बार-बार क्रोप इंश्योरेन्स का सवाल उठाया जाता है। यह भी कहा जाता है कि फसल बीमा करके किसानों को मदद पहुंचाई जाय। यह फसल बीमा स्कीम आप नेशनल लेवल पर लागू करेंगे या नहीं? इस पर गम्भीरता से आप क्या विचार करेंगे और आपके चीफ मिनिस्टर्स जितने हैं स्टेट के, पिछली दफा, कल ही की बैठक में इस बारे में विचार विमर्श किया है या नहीं, यह तीसरा सवाल है?

चौथा और आखरी सवाल यह है कि चीफ मिनिस्टरों ने कीमतें बताई हैं अपने अपने राज्यों के मुताबिक। सबों में मोटे-तौर पर, जिस तरह की बातें अखबारों में आई हैं 100 से ज्यादा हीं, 104 से लेकर 140 तक की बात की है। अब आप यह बतायें कि एवरेज कितना आप प्राइमाफेसी रीजनबेल समझते हैं। एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन है ही उसको सप्लीमेन्टरी रिपोर्ट आपको देनी चाहिये। चीफ मिनिस्टर्स की तरफ से जो प्रस्ताव है उसके मुताबिक इतने से काम नहीं चलेगा। वह उसको बढाकर 140-150 तक करना चाहते हैं। तो आप यह नहीं महसूस करते है कि यह रिकमन्डेशन जो है सौ रुपये यह बहुत कम है और मिनिमम यह 125-130 जरूर होनी चाहिये। तो मेरा सवाल है कि कब तक आप इस सजेशन के मुताबिक एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन को कहने जा रहे हैं कि वह कब तक अपनी रपट दे दे इसके कान्टेक्स्ट में जो सजेशन आये है, यह मेरा चौथा सवाल है।

राव बिरेन्द्र सिंह : एक के बाद एक माननीय सदस्य पूछ लें, मैं बाद में सब का जवाब दे दूंगा।

उपसमाध्यक्ष (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : आप जवाब दे दीजिये।

राव बीरेन्द्र सिंह : एक एक सवाल का जवाब . . .

उपसभाध्यक्ष (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : उनके चार सवाल हैं।

राव बीरेन्द्र सिंह : उनका पहला सवाल है कर्जे के बारे में। तो मैंने पहले ही अर्ज कर दिया है कि श्री कल्पनाथ राय की तजवीज मुझे बहुत अच्छी लगी कि एक सही सर्वे सारे हिन्दुस्तान का कराना चाहिये और मैं पहले ही कह चुका हूं कि इस वक्त हमारे पास कोई सही फिगर्स नहीं है कि कितनी इनडेटेडनेस किसानों के ऊपर इस वक्त है, क्या हालत है और उनका कितना एरियर्स है। अखबारों में जरूर आता है कि तमिलनाडु की सरकार ने कई करोड़ रुपये रेमेट करने के लिये तजवीज की है और सेन्ट्रल गवर्नमेंन्ट को पूछा है, महाराष्ट्र गवर्नमेन्ट ने तजवीज की है कि हम भी उनका कर्जा माफ करते हैं। इस तरह की रिपोर्ट तो है लेकिन हमारे पास सही ब्यौरा इस बारे में नहीं है। इसके लिये श्री कल्पनाथ राय ने जो तजवीज रखी है उसको मंजूर किया है और हम उस सिलसिले में जरूर कदम उठाना चाहते हैं कि हम सही सर्वे करायें। किसानों की हालत और जहां तक कर्जे के भार का ताल्लुक है। *(Interruptions)*.

श्री शिव चन्द्र झा : आपने फरमाया कि पैदावार घट गई।

उपसभाध्यक्ष (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : फूड ग्रेन की पैदावार।

राव बीरेन्द्र सिंह : फूड ग्रेन की जो पैदावार है उसके लिये वे समझते हैं कि क़ीमतें मुनासिब नहीं मिली इस वास्ते पैदावार घट गई। मैं इस चीज से सहमत नहीं हूं। पिछले सालों में सरकार ने जो सुविधायें किसान को दी हैं, जिस तरह से सिंचाई को बढ़ाने के लिये खर्चा किया तो काफी जमीन हम नई और सिंचाई के नीचे ले रहे हैं। इस साल के अन्दर 27 मिलियन हेक्टर में और सिंचाई का प्रबन्ध करने की हमारी योजना है। तो यह सारा इन चीजों के ऊपर खर्च होता है, किसान को जो बिजली मिलती है उस पर भी भारी खर्चा होता है, ट्यूब वेल जो लगाये जाते है उन पर भी खर्चा होता है दूसरी चीजों में केवल सब्सिडी ही खाली नहीं, प्राइस ही नहीं जो किसान को सहूलियत के तौर पर मिलती है किसानों के लिये बहुत सी योजनाओं में पैसा खर्च होता है। किसान को ठीक कीमतें मिल रही हैं और उसकी पैदावार में बचत रही है, नुकसान नहीं रहा। जनरली, वह फायदा उठाता रहा है इसलिए हमारा प्रोडक्शन फूड ग्रेन का हर साल बढ़ता ही रहा है। पिछले साल की बात दूसरी है। ड्राउट की वजह से पैदावार में कमी जरूर आई।

श्री शिव चन्द्र झा : क्राप्स एकड़ेज के बारे में भी बताइये? एक ही जगह एक ही एकड़ में आप ज्यादा पैदा कर सकते हैं।

राव बीरेन्द्र सिंह : एकड़ेज में ही हमारी क्राप्स ज्यादा बढ़ी है। कहीं कहीं किसी क्राप्स के अन्दर एकड़ेज घटा है। लेकिन कल्टीवेटेड लैण्ड जो है और जैसा कि वह कुछ फालतू पड़ा ही रहता है, कल्टीवेटेबाईबल एरिया भी स्माल है जैसा कि आप समझते है कि जंगल घटते आ रहे हैं, बंजर जमीन के ऊपर हल चलाना शुरू है कुछ पड़ी है। इस प्रकार जहां टोटल एकड़ का ताल्लुक है वह बढ़ा है। जहां मुखतलिफ फसलों के दरम्यान पैदावार का सवाल है इसके आंकड़ें मैं नहीं दे सकता लेकिन मैं एक बात का यकीन दिलाता हूं कि कोई जमीन ऐसी नहीं है जो काबू में किसान

कर सके और उसमें वह बोना न चाहता हो। सिर्फ कम कीमत की वजह से किसी ने कोई जमीन बोने से छोड़ दी हो, यह आपका ख्याल गलत है। यह दूसरी बात है कहीं किसी किसान को गन्ने में कम आमदनी दिखाई देती है तो वह पेड्डी लगा लेता है कहीं उसको तेल वाले बीजों में कीमत बढ़ती दिखाई देती है तो वह उसको खेती करता है। या ईल्ट कम दिखाई देती है तो वह कपास लगाना शुरू कर देता है, कोई दूसरी फसल कर लेता है। तो इस तरह से हर साल टोटल एक्रेज में तबदीली होती रहती है। लेकिन आमदनी किसान को खासी है। इस वास्ते पैदावार बढ़ती जा रही है। कपास की भी पैदावार बढ़ी है और इस साल और भी बढ़ने की उम्मीद है। गन्ने की पैदावार बढ़ती जा रही है, चावल की भी बढ़ी है। तेल निकालने के बीजों की, दालों की पैदावार बढ़ी है। हर चीज की पैदावार पल्सेज और आयल-सीड्स की पैदावार बढ़ती ही चली गई है और इस मामले में आपको परेशान नहीं होना चाहिए।

श्री शिव चन्द्र झा : अब क्रेश आप के एक्रेज के बारे में भी बता दें।

राव बीरेन्द्र सिंह : जहां तक क्राप इंश्योरेंस का सवाल है मैं यह कहना चाहता हूं कि क्राप इंश्योरेंस स्कीम एज सच अभी लागू नहीं हुई है। इसमें बहुत सी कठिनाइयां हैं। लेकिन कुछ पाइलट प्रोजेक्ट्स इस मामले में शुरू किए गए हैं। गुजरात और तमिल नाडु, मुझे सही तो नहीं अगर इस मामले में गलती हो तो मैं माफी चाहूंगा कि शायद वेस्ट बंगाल में, तीन स्टेट्स के अन्दर कुछ पाइलट प्रोजेक्ट्स क्राप इंश्योरेंस शुरू हुए हैं। कुछ फसलों के ऊपर शुरू हुए हैं। यह भी जनरल इंश्योरेंस कम्पनी ने शुरू किए हैं। स्टेट गवर्नमेंट से बात कर के सेंट्रल गवर्नमेंट की मंजूरी लेकर कि जो कर्ज किसानों को दिया जाता है उसकी इंश्योरेंस की जाती है। क्राप का फेलयर हो उस मामले में करते हैं। जहां तक प्रिमियम का ताल्लुक है उस मामले में 50% तो किसान देता है, 25 फीसदी स्टेट गवर्नमेंट और 25 फीसदी सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। हम ने इस स्कीम को और बढ़ाने के लिए हर स्टेट गवर्नमेंट को लिखा है। मैंने खुद चीफ मिनिस्टर्ज को लिखा है, जब से हमारी गवर्नमेंट बनी है तभी लिखा है। हमें इसको और आगे बढ़ाना चाहिए इससे आहिस्ता आहिस्ता हम स्टेट सेक्टर में क्राप इंश्योरेंस के मामले में कहां तक आगे बढ़ सकते हैं, तरक्की कर सकते हैं।

चौथी बात, उन्होंने मेरे से एक जाति सवाल किया है कि मेरी राय में कीमत क्या होनी चाहिए। मैं तो अपनी राय जाहिर नहीं कर सकता इस मामले में, मैं बहुत मजबूर हूं मैं जो आपकी राय होगी, चीफ मिनिस्टर्ज साहेबान की राय होगी और जो रिपोर्ट एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन की है इस सब को केबीनेट के सामने पेश करने का जिम्मेदार हूं। और वहां कोई मेरी अपनी राय नहीं होगी। जैसे केबीनेट की राय होगी वह मेरी राय होगी। मेरी राय कोई अलग से नहीं हो सकती है और न ही मैं इस वक्त कोई जाहिर कर सकता हूं।

श्री नागेश्वर प्रसाद शाही (उत्तर प्रदेश) : आप अपनी क्या राय केबीनेट को देंगे।

उपसभाध्यक्ष (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : आप बैठिये। (*Interruptions*).

श्री नागेश्वर प्रसाद शाही : आप अपनी केबीनेट को क्या राय देंगे ? (*Interruptions*).

उपसभाध्यक्ष (श्री सवाई सिंह सिसौदिया) : आप बैठिये, मंत्री जी को सुनिये ।

(Interruptions)

श्री नागेश्वर प्रसादशाही : इसलिएमैं कहता हूं। On a point of order, Sir. The Minister has to give his own opinion before the Cabinet.

उपसभाध्यक्ष (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : यह कोई प्वाइंट आफ आर्डर नहीं बनता ।

श्री नागेश्वर प्रसाद शाही : यह प्वाइंट आफ आर्डर है, श्रीमन् ।

उपसभाध्यक्ष (श्री सवाई सिंह सिसोदिया): प्वाइंट आफ आर्डर नहीं है ।

श्री नागेश्वर प्रसाद शाही : मंत्री जी ने यह कह दिया कि जो केबीनेट की राय होगी, वह मेरी राय होगी । यह तो केबीनेट के डिसीजन के बाद होता है। केबीनेट के डिसीजन . . .

उपसभाध्यक्ष (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : आप बैठिये ।

श्री नागेश्वर प्रसाद शाही : आप सुनिये तो। केबीनेट के डिसीजन के पहले मंत्री जी को ड्यूटी है कि अपनी राय केबीनेट को बताए ।

RAO BIRENDRA SINGH: It is never the practice in any legislature that questions are raised on the point of personal opinion of a Minister or a Member, This is my personal opinion and Cabinet proceedings zan-nat be disclosed.

श्री हुक्मदेव नारायण यादव (बिहार) : उपसभाध्यक्ष महोदय, जो खेती के उत्पादन की कीमत तय करने का सवाल है, श्री कल्पनाथ राय जी ने इस बारे में कुछ प्रश्न उठाए, मैं उनके प्रश्नों को सुन भी रहा था । संगति से व्यक्ति के विचार भी बदल जाते हैं ।

उपसभाध्यक्ष महोदय, एक जमाना था जब हम और कल्पनाथ राय जी इस गल्ले के दाम के सवाल को लेकर एजीटेशन करते थे और हमारा नारा होता था :

"अन्न दाम का घटना बढ़ना, आना सेर के अंदर हो, डेढ़ गुने की लागत पर कड़खनियां माल की बिक्री हो"

इस सवाल को लेकर कई बार हम लोग साथ साथ जेल भी गये थे । आज उन सवालों को उठाने का सवाल है कि सिर्फ गल्ले की कीमत नहीं साथ ही साथ देश में अन्य चीजों की कीमत बांधने के लिए सरकार की तरफ से ठोस मूल्य नीति होनी चाहिए । कारखाने के माल की कीमत और खेतिहर माल की कीमत, इन दोनों को बांध देना चाहिए और उनमें अनुपात होना चाहिए कि गल्ले की कीमत एक फसल से दूसरी फसल के बीच कितनी बढ़े तथा कारखाने से जो उत्पादन है उसकी कीमत कितनी बढ़े । क्या सरकार इस बात को या इस मूल्य नीति को मानने के लिए तैयार है ।

जब किसान के खेतों में गल्ला पैदा होता है तो उस समय फसल की कीमत बाजार में कम रहती है और जब हम गल्ला बेच देते हैं तो या तो सरकार खरीद लेती है या व्यापारी खरीद लेता है । परन्तु फिर दूसरी फसल आने तक उस गल्ले की कीमत में डेढ़गुनी या पौने दो गुनी वृद्धि हो जाती है । जब हम फसल बेचें तो कम कीमत पायें और जब हम खुद खरीददार बनकर जायें तो डेढ़ गुनी या दो गुनी कीमत पर वहां से खरीदें । क्या सरकार के पास इसको रोकने के लिए कोई नीति है, उपाय है या कोई योजना है। फिर कारखाने के माल की जो कीमत है वह जितनी उत्पादन लागत है उससे डेढ़ गुना लागत से अधिक लागत पर हिन्दुस्तान के किसी कोने के बाजार में न मिले क्या इसके बारें में सरकार के पास कोई ठोस नीति है या नहीं ।

अभी कल्प नाथ राय जी ने गन्ने की कीमत के बारे में कहा । वे शायद भूल रहे हैं कि जब जनता सरकार बनी थी तो गन्ने की कीमत साढ़े 10 रुपए क्विंटल तय की गयी थी । चौधरी चरण सिंह जी के समय में साढ़े 12 रुपए क्विंटल तय की गयी । जनता सरकार पहली सरकार थी जिसने हमारे बिहार के अंदर किसानों ने जितना गन्ना मिलों को दिया था उस पर प्रति क्विंटल अढ़ाई रुपए के हिसाब से किसानों को दिया था । जितना मिलने दिया, और उस पर प्रति क्विंटल अढ़ाई रूपये के हिसाब से सरकार ने सीधे किसानों को भुगतान किया था । यह हमारे यहां हुआ था । फिर साढ़े 12 रुपए से लेकर साढ़े के 16 रुपए तक.

उप-सभाध्यक्ष (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : जानकारी देने के बजाय सवाल पूछिये ।

श्री हुक्म देव नारायण यादव : उन्होंने कहा कि जनता सरकार की गड़बड़ी से हुआ... *(Interruptions)*.

उप-सभाध्यक्ष (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : आप प्रश्न पूछिए *(Interruptions)*.

श्री हुक्मदेव नारायण यादव : तो मैं कैसे सुन लूं और उसका जवाब न दूं ।

उप-सभाध्यक्ष (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) जवाब आप नहीं देंगे, मंत्री जी देंगे ।

श्री हुक्मदेव नारायण यादव : उन्होंने जवाब दिया. . *(Interruptions)*. उन्होंने लोकदल और जनता सरकार का नाम लिया । अब उस सरकार का जवाब कौन देगा । उनकी तरफ से मैं ही बोलूंगा । इसलिए, उपसभाध्यक्ष महोदय, वह उस समय की बात है ।

मैं कृषि मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि 33 रुपए गेहूं पर और 26 रुपए चावल पर देते हैं । भारतीय खाद्य निगम 27 प्रतिशत मुनाफा लेता है, भारतीय खाद्य निगम 27 प्रतिशत तक मुनाफा लेकर बाजार में बेचे और ऊपर से 33 रुपए गहूं पर तथा 26 रुपए चावल पर सब्सिडी कन्ज्यूमर को दे परन्तु फिर भी सवा 6 सौ करोड़ रुपए भारतीय खाद्य निगम की घाटा पूर्ति के लिए आपको देना पड़े तो यह जो भारतीय खाद्य निगम व्यापार कर रहा है इससे किसान का कितना शोषण हो रहा है और कन्ज्यूमर का कितना हो रहा है, इसकी जांच करने के लिए एक कमेटी बिठाईये कि वह शोषण कहां हो रहा है या नहीं ।

फिर इसके जरिए मैं यह सवाल करना चाहूंगा कि इन्होंने कहा कि साढ़े 6 करोड़ रुपया प्याज के ऊपर नाफेड को दिया । साढ़े 6 करोड़ रुपया नाफेड को दिया तो स रुपए में से किसानों को कितना मिल पाया । हमको तो यही सोचना है कि किसान को कितना जाता है। यह नाफेड इत्यादि तमाम जो सरकारी कारोबार करने वाले संस्थान हैं, उन संस्थाओं के अंदर उनकी व्यवस्था पर, उनके परिचालन पर जो घाटा या नुकसान होता है उसको पूरा करने के लिए जो भी पैसा आप देते हैं वह किसान तक तो जाता नहीं है बल्कि कुछ लोग ऐसे हैं कि वह पैसा ऊपर ही ऊपर चला जाता है और किसान बेचारे को उससे कुछ मिलता नहीं है, उल्टे नुकसान होता है । क्या आप उस घाटे की पूर्ति करते हैं ? उल्टे हम पर टैक्स बढ़ा देते हो उस घाटे की पूर्ति के लिए तो हम दोनों तरफ से आ रहे हैं। इसलिए सरकार को इसकी जांच करानी चाहिए ।

[श्री हुक्म देव नारायण यादव]

सरकार से मैं यह कहना चाहता हूं कि कृषि का उत्पादन जो है उसका बाजार जब तक किसान के हाथ में नहीं रहेगा और जब तक राज्य और व्यापारी के हाथ में बाजार का नियंत्रण रहेगा तो यह ठीक नहीं रहेगा। चौधरी चरण सिंह जी जिस समय वित्त मंत्री बने थे उस समय जनता पार्टी की सरकार ने अपने बजट में एलान किया था कि हर पंचायत में हम गोदाम बनायेंगे। इन गोदामों में किसान अपना गल्ला रखेगा और इस गल्ले से किसान बैंकों से कर्ज ले लेंगे। जब बाजार में उसकी कीमत आयेगी तो फिर उस गल्ले को बेच देंगे। जैसे कि व्यापारी गोदामों में अपना माल रखते हैं और उस पर वे 80 परसेंट, 70 परसेंट या 60 परसेंट लोन ले लेते हैं और अपना कारोबार करते हैं उसी तरह से किसानों को भी सुविधा मिलनी चाहिए कि हम गोदामों में अपना गल्ला रख दें और 70 या 80 परसेंट गल्ले की कीमत के अनुपात में बैंकों से कर्ज लेकर अपना काम कर लें। फिर जब बाजार में हमें उसकी कीमत मिलेगी तो हम उस समय उसको बेच सकेंगे। सरकार की वह योजना, जो गोदाम बनाने की जनता सरकार के समय में बनाई गई थी, उस योजना को सरकार खटाई में क्यों डाल रही है। उसको बनाने के लिये सरकार का क्या दृष्टिकोण है? वह गोदाम वाली योजना कहां चली गई है?

अंतिम सवाल पूछना चाहूंगा, कृषि मंत्री जी भी यहां बैठे हुए हैं, दुनिया के अन्दर वह देश सब से शक्तिशाली देश माना जाता है जहां कृषि पर भार सब से कम है। जहां रूस में 31 प्रतिशत आदमी खेती पर लगा हुआ है, लगभग साढ़े इकतीस प्रतिशत, अमरीका में चार प्रतिशत आदमी खेती पर है, इंग्लैंड में अढ़ाई प्रतिशत आदमी खेती पर है, जापान में 20 प्रतिशत आदमी खेती पर लगा हुआ है, वहां भारत में 70 प्रतिशत आदमी खेती पर लगा हुआ है। अमरीका, इंग्लैंड, जापान, रूस (*Interruptions*)

उपसभाध्यक्ष श्री सवाई सिंह सिसोदिया): खत्म कीजिए। काफी टाइम हो गया है। समाप्त कीजिए।

श्री हुक्म देव नारायण यादव : खेती पर से भार कम करने के लिए और खेती पर जो लगे हुए हैं, उनको दूसरे उद्योग धंधों में लगाया जाए, कुटीर उद्योगों को गांव में बिठाया जाए और किसानों को खेती के साथ-साथ कोई दूसरा रोजगार भी दिया जाए, इसके बारे में इनके पास कोई योजना है कि नहीं? अगर नहीं है, तो मैं यह कहूंगा कि दीर्घ कालीन नीति रही है और भारत सरकार जो आजादी के बाद से चलती रही, प्राथमिकताओं का निर्धारण नहीं हुआ और प्राथमिकताओं का निर्धारण नहीं होने के कारण किसान की ओर उपेक्षा होती रही।

अब इन्होंने कहा है कि भगवान खुश है—जब इन्द्र महाराज ने पानी बरसा दिया तो खुश हैं। अगर इन्द्र पानी न बरसायें तो गाली दिया जाए और पानी बरस जाए तो इन्दिरा जी की जय-जयकार किया जाए—यह आपकी नीति रही है।

राव बीरेन्द्र सिंह : शुगरकेन के मुतल्लिक, उपसभाध्यक्ष जी, श्री हुक्मदेव नारायण यादव जी ने कहा, पर शुगरकेन के मुतल्लिक डिसकशन तो नहीं था, लेकिन कुछ सवाल उठाये। तो शुगरकेन प्राइस की नीति भी सारी चीजों का जायजा लेकर पूरी तरह से, कितना कास्ट आफ प्रोडक्शन है, कितना फैक्ट्रीज को लाभ होता है और किसान को उसके मुताबिक पैसा दिलवाया जाता है, वक्त पर दिलवाया जाता है, उसके अलावा एक और बंदोबस्त सरकार ने किया है कि अगर किसी वजह से फैक्ट्री मालिक ज्यादा फायादा कमा लेता है शुगर बनाने के बाद, तो उसमें से जितना अधिक फायदा हो, जिसका पहले

अंदाजा लगाया गया था, उसमें से आधा-आधा पैसा तकसीम होगा, आधा फैक्ट्री के पास रहेगा और आधा किसान को फालतू प्राफिट में से भी देना पड़ेगा । तो इस लिहाज से भूगरकेन ग्रोअर्ज की तरफ पूरा ध्यान दे रहे हैं ।

एफ० सी० आई० कहाँ से कितना प्राफिट लेती है, वह आनरेबल मेंबर को कहां से इत्तिला मिली--मेरे पास तो यह जानकारी नहीं है । यह सब्सीडी जो फूड के ऊपर दी जाती है, यह तो नुक्सान होता है एफ०सी० आई० को इतने पैसे पर चावल और गेंहू तकसीम करने में उस नुक्सान को पूरा करने के लिए दिया जाता है । तो 27 रुपये फी क्विटल एफ० सी० आई० के लिए सवाल ही पैदा नहीं होता :

श्री हुक्मदेव नारायण यादव : 27 प्रतिशत ?

राव बीरेन्द्र सिंह : 27 प्रतिशत तो क्या, एक प्रतिशत का भी सवाल नहीं पैदा होता । तो घाटे को पूरा करने के लिए सरकारी खजाने से दे रहे हैं, तब एफ०सी०आई० के मुनाफे का उसमें कहाँ से आ गया ।

ओनियन दाम के ऊपर जो छह करोड़ रुपया सरकार ने दिया है, इसको सारा फायदा किसान को पहुंचाने की गर्ज से यह रकम मिल रही है । प्याज की कीमत जब रु० 25-30 के करीब आ गई थी और किसान परेशान था, बिक्री नहीं थी, तो सरकार ने हुकम दिया कि वह प्याज नफेड रु० 45-50 के भाव पर खरीद करे तो यह जो रु० 30 के करीब फालतू फी क्विटल पैसा नफेड की तरफ से सरकार ने दिया है और यह जो दुगने पैसे पर जो प्याज खरीदा मंडी के भाव से, यह फायदा किसान को पहुंचे, तो यह बड़ी सीधी सी समझने की बात है । यह सब किसान के फायदे के लिए ही छह करोड़ रुपया से ऊपर दिया गया है, यह नफेड के लिए नहीं दिया गया । अगर अब नफेड के पास जो प्याज का स्टाक हो गया है, उसको बेचने से कोई फायदा हो जाएगा तो वह नफेड के पास जमा रहेगा और सरकार उस पैसे से नफेड को कोई और काम किसान के हित में करने के लिए हुकम देगी । वह उसके पास फंड जमा रहेगा । तो यह सब किसान कि सुविधा के लिए किया गया है ।

रूरल गोडाउंस की बहुत पुरानी स्कीम है । हम इसको बढ़ाना चाहते हैं कोआपरेटिव के जरिए और अगले सालों के अन्दर छटी पंच-वर्षीय योजना के अंदर हम बहुत काफी, कितने लाखों टन की कैपसिटी रूरल गोडाउंस की बना रहे हैं । यह स्कीम हमने छोड़ी नहीं है ।

1 P.M.

श्री राम लखन प्रसाद गुप्त (बिहार) : उपसभाध्यक्ष महोदय, अभी माननीय मंत्री जी ने राय मांगी भी है कि क्या कीमत होनी चाहिये । मेरी राय में इस वर्ष धान की कीमत किसी भी हालत में 120 रु० क्विटल से कम नहीं होनी चाहिये, ज्यादा जो भी हो उसके लिए मेरा आधार यह है कि धान की कीमत पिछले दिनों जो तय हुई हैं वह 1977-78 में 77 रु० क्विटल, 1978-79 में 85 रु० क्विटल, 1979-80 में 95 रु० क्विटल, 1980-81 में 100 रु० क्विटल भी उन्होंने रखी है । लेकिन होल सेल प्राइस इन्डेक्स जो बढ़ा है, उसमें चावल का भी प्राइस इन्डेक्स बड़ा दिखाया है, रिपोर्ट के अनुसार मार्च, 1977 में वह था 156.2, 1978 में 148.8, 1979 में 157.6 और 1980 में 179.9 है । इस तरह से जो होलसेल प्राइस इन्डेक्स चावल बढा है उस हिसाब से यह कीमत 120 रु० क्विटल धान की अवश्य ही होनी चाहिये । इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट और अग्रिकल्चरल प्रोडक्ट में 20 परसेन्ट का गैप रहा है, रिपोर्ट के अनुसार । यह 20 परसेन्ट का गैप यह बताता है कि अगर 100 क्विटल जो सजेस्ट किया है यह 120

[श्री राम लखन प्रसाद गुप्त :]

रु० क्विंटल होना ही चाहिये । इसलिए मेरा पहला प्रश्न यह है कि सब बातों का विचार करते हुए 120 रु० क्विंटल बहुत ही उचित भाव है और क्या मंत्री महोदय इसको उचित समझते हैं या 120 रु० से भी ऊपर जाने की सोचते हैं ?

दूसरा प्रश्न है कि यह बात सही है कि जब गेहूं की बंपर क्राप हुई तो उसके बाद से जो पहले लेवी प्राइस हुआ करती थी उसको सपोर्ट प्राइस में बदला गया और उसके बाद अग्रिकल्चरल प्राइस कमीशन का गठन भी हुआ और अब अग्रिकल्चरल प्राइस कमीशन कीमत को तय करता है लेकिन उपसभाध्यक्ष महोदय, हमारे बिहार में पिछले वर्ष और उसके पहले भी 12,000 टन चावल की उगाही हुई है । आज बिहार के अन्दर यह सपोर्ट प्राइस न होकर लेवी प्राइस के रूप में अभी भी कंटिन्यू कर रहा है । वहां एक किसान को 35 रु० क्विंटल के हिसाब से लास होता है या व्यापारी को 35 रु० का लास लेवी में देना पड़ता है । तो क्या मंत्री महोदय यह सोचते हैं कि जब सारे हिन्दुस्तान के लिए सपोर्ट प्राइस है तो बिहार में लेवी प्राइस के रूप में न हो और 35 रु० क्विंटल का घाटा वहां के किसानों और व्यापारियों को न हो ।

तीसरी बात, यूरिया की कीमत 38 प्रतिशत बढ़ी और 1450 रु० – 2000 रु० टन कीमत बढ़ी है, डीजल की भी कीमत 50 प्रतिशत बढ़ी है इसलिए रासायनिक खाद, वाटर सप्लाई और इरिगेशन के मामले में जो दिक्कतें हुई हैं बिजली की कमी के कारण, और मजदूरी में जो रेट बढ़ा है, इन सब चीजों को खयाल में रखते हुए कीमतें किसी भी तरह से 120 रु० से कम नहीं होनी चाहिये ।

उपसभाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने चीनी के बारे में कहा । उन्होंने कहा कि हम स्वागत करेंगे चीनी की कीमत कम करने का सुझाव कोई देवे तो । मैं दो बातें पूछना चाहता हूं मंत्री महोदय से । मिलें पहले चीनी 400–450 रु० क्विंटल बेचती थीं, उसी चीनी मिलों ने 850 रु० कर दिया और बाजार में चीनी का भाव 9 से 10 रु० किलो का है । तो क्या आपका जो प्रिवेंटिव डिटेन्शन कानून बना है वह इसमें अमल नहीं आ रहा है ? हन्डरेड परसेन्ट प्राफिट, 400 रु० क्विंटल की चीनी वही मिलें 800 रु० में बेचती है, क्या यह प्राफिटियरिंग नहीं है ? आपने कितने मिल मालिकों को प्रिवेंटिव डिटेन्शन में लिया है । दूसरी चीज, उस रोज बहस मे बात आई थी . . .

उपसभाध्यक्ष (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : शक्कर पर बहुत बहस हो चुकी है ।

श्री रामलखन प्रसाद गुप्त : एक अन्तिम बात कहनी है । उस समय यह कहा गया कि किस तरह कोटा बनता है और मिल मालिक तुरन्त डिलीवरी दे देते हैं । क्या मंत्री महोदय को यह पता है कि ये सभी मिल-मालिक अपने अपने आदमी को मोनोपोलिस्ट बहाल किये हैं और अपने यहां की मिल की डिलीवरी उस मोनोपोलिस्ट के नाम दिखला देते हैं और . . .

मोनोपोलिस्ट ट्रेडर्स से पैसा लेकर, लेट डिलीवरी करते हैं । यह मैन मेड क्राइसिस है ।

उपसभाध्यक्ष (श्री सवाई सिंह, सिसोदिया) : अब समाप्त भी कीजिये ।

श्री रामलखन प्रसाद गुप्त : हो तो गया । बस इतना ही जानना चाहता था ।

श्री कल्पनाथ राय : बहुत रिलेवेन्ट सवाल है ।

राव बीरेन्द्र सिंह : सवाल तो रिलेवेंट नहीं । आप जानते हैं कि सवाल तो उठाया गया था केवल धान की कीमत का ।

श्री रामलखन प्रसाद गुप्त : चीनी का सवाल आपने ही उठाया है ।

उपसभाध्यक्ष (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : गुप्त जी, जवाब तो सुनिये ।

राव बीरेन्द्र सिंह : मुझे एतराज नहीं जवाब देने में अगर माननीय वाइस चेयरमैन साहब इजाजत देंगे तो।

पहला तो सवाल यह ही है माननीय सदस्य का, सुझाव है कि 120 रु० क्विटल धान की कीमत जरूर मुकर्रर की जाये । सुझाव तो इस तरह के सब तरफ से आए है, हाउस में भी आए, बाहर से भी आए, चीफ मिनिस्टर्स से भी बात हुई है, किसी की कुछ राय है, किसी की कुछ राय है । मैं यही अर्ज कर सकता हूं कि पहले भी धान की कीमत हमेशा मुनासिब तय करने की बात सरकार ने सोची । सन् 76–77 में 74 रु० धान की सपोर्ट प्राइस मुकर्रर हुई थी । पिछले साल 95 रुपये कर दी गई । यह कोई 29 परसेन्ट की बढ़ोत्तरी हुई तीन सालों के अन्दर । तो धान की कीमत काफी हद तक बढ़ी है । इतनी गेहूं की नहीं बढ़ी । इस मामले में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिये । अब भी कीमत ऐसी तो होगी जिससे किसान को मुनाफा मिल सके और घाटा किसी भी हालत में न हो ।

बिहार में लेवी सिस्टम क्या है चावल के बारे में मुझे जानकारी नहीं है. इसलिए इस सिलसिले में मैं कुछ नहीं कह सकता । लेकिन यह जरूर है कि ए० पी० सी० की रिकमेंडेशन से कीमत जो तय होती है वह मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, किसी के लिए लाजिमी नहीं है कि उस कीमत पर बेचे । अगर उतनी कीमत उसको नहीं न मिले तो सरकार की तरफ से गारन्टी है कि उसके माल को इतनी कीमत पर जरूर उठाया जाएगा मंडी से । उसके ऊपर कोई पाबन्दी नहीं है । वह हिन्दुस्तान के किसी हिस्से ले जाकर ज्यादा कीमत के ऊपर बेच सकता है इसलिए घाटा होने का सवाल नहीं उठता । यह मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उसकी मदद के लिए । अगर वह इस कीमत पर बेचना चाहे तो सरकार खरीदने के लिए तैयार रहेगी । अगर उसको इस प्राइस पर बेचना मंजूर नहीं तो वह कहीं ले जाकर बेच सकता है । इसमें उसे पूरी फ्रीडम है कोई पाबन्दी नहीं है । जोन्स पहले से एवालिश हो चुके हैं ।

मैं बिल्कुल इस बात से सहमत नहीं हूं कि बिहार में किसानों को चावल के ऊपर 35 रुपए फी क्विटल नुकसान हो रहा है । अगर नुकसान हो रहा है तो किसान की बेसमझी की वजह से हो रहा है, माननीय सदस्य उनको समझायें कि क्या कायदे कानून हैं, किस तरह सरकार उनकी मदद करती है और उनको बचायें नुकसान से ।

शुगर के बारे में जिक्र किया माननीय सदस्य ने । 35 परसेंट शुगर माफ है शुगर फैक्टरीज के लिए, प्रोड्यूसर्स के लिए, 65 परसेंट की लेवी है। लेवी प्राइस तय हो चुकी है । 65 परसेंट 2 रु० 85 पैसे पर हम तक्सीम करते हैं राशन की दुकानों से । सारे मुल्क के अन्दर हर व्यक्ति को मिलती है जितनी एवेलेबिल होती है। बाकी 35 परसेंट छोड़ी गई है प्रोड्यूसर्स के लिए कि वे फी मार्केट में चाहे जितने दाम पर बेचें । उसकी कीमत के ऊपर सरकार कोई पाबन्दी नहीं लगा सकती क्योंकि यह 65

[राव वीरेन्द्र सिंह]

फीसदी उनके कास्ट प्राइस से कम पर खरीदी जाती है और उसका नुकसान वे 35 परसेंट बेच कर पूरा करते हैं। सारी सोसायटी के पुअरर सेक्शन्स को बहुत कम कीमत पर, 2 रु० 85 पैसे पर, कुछ न कुछ चीनी मिल सके इस वास्ते ये कायदे बनाए गए हैं।

श्री राम लखन प्रसाद गुप्त : उपसभाध्यक्ष जी . . .

उपसभाध्यक्ष (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : गुप्त जी, ऐसे कैसे चलेगा। पहले आप पूरी बात सुनिये (*Interruptions*) आप मेहरबानी कर के बैठ जाइए।

राव वीरेन्द्र सिंह : एक बार छूट देने के बाद सरकार इस बात पर किसी को नहीं पकड़ सकती कि वह ज्यादा कीमत पर अपनी फ्री कोटे की चीनी क्यों बेचता है। दूसरी पाबन्दियाँ लगायी गयी हैं। स्टाफ 250 क्विंटल से ज्यादा किसी व्यापारी, किसी होलसेलर के पास भी न हो। दस दिन से ज्यादा वह किसी फैक्टरी से चीनी ला कर अपने गोदाम में या दुकान में नहीं रखेगा। सिर्फ इस इंतजार में कि कीमत बढ़ जाएगी तब बेचेंगे। मार्केट में चीनी आती रहे और बिकती रहे इसके लिए हमने कायदे कानून बनाये हैं और जो इन कानूनों को तोड़ता है उसको पकड़ते हैं। छापे भी मारे जा रहे हैं, प्रिवेंटिव डिटेंशन ऐक्ट में भी लोगों को पकड़ा गया है मुख्तलिफ सूबों में और सजायें भी उनको मिली हैं और अब हमने खंडसारी पर भी यह पाबन्दी लागू कर दी है जो पहले नहीं थी। खंडसारी की मिलों पर भी पाबंदी लगा दी है। रेड किये जा रहे हैं और जहाँ कहीं वह पकड़ में आयेंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा।

श्री रामलखन प्रसाद गुप्त : एक क्लैरिफिकेशन चाहता हूं। एशेंसियल कमोडिटीज ऐक्ट में प्राफिट की बात है . . . (*Interruptions*).

उपसभाध्यक्ष (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : आप बैठिये।

SHRI K. CHATHUNNI MASTER (Kerala): For the last so many years, the whole section of our peasantry of India, is demanding a fair, remunerative price for their produce. For the last so many years they are fighting for this legitimate demand. Finally, the A.P.C. gave a wonderful recommendation. According to our peasant, the A.P.C. is a wonderful type of creation, Sir. God alone knows what are the facts they are taking into account to fix the price of agricultural produce. Our Minister argued on scientific basis here. What are the scientific basis? What are their recommendations? Please furnish some data.

Within a week, after the Indian Budget, a very sweet Budget of our Finance Minister Mr. Venkataraman, was presented, the wholesale price index has made an unprecedented lead of 4.'5 per cent. Between, February 1978 and June 1980, the phenomenal rise of the wholesale price index was about 30 per cent. Besides, the ever widening disparity between the prices of agricultural produce and industrial products has been still widening. This disparity in prices rose from 4.4 per cent in 1978-79 to 14.2 per cent in 1979-80. During the first three months of the Congress (I) rule there was an alarming growth of this disparity from 16 per cent to 19.8 per cent. In this situation, God alone knows,, Sir, what are the scientific facts the A.P.C. is taking into consideration to fix the agricultural prices? Their new proposal is to increase it by Rs. 5/- per quintal. Sir, this is not only a most unjustifiable policy, but this is a most ignominous policy of the Government also, I think. Sir the agitated peasants are crying for a legitimate price, a fair price,, a remunerative price, for their produce.

They are going en an agitation. What is happening ..

THE VICE-C HAIRMAN (SHRI SAWAISINGH SISODIA). Please come to the poin . Ask questions.

SHRI K. CHA' HUNNI MASTER: Shootings are gc 'ng on. In Mysore State they have t Iready killed 11 persons. In Mahar; shtra, in another shooting by the police, 2 persons were killed This is the policy of 'lathi' and bullets. Is it tolerable, Sir? My question is: is the Minister prepared to assure this House' Once there was an assurance from 1 ie Government that the prices will *i* iways be announced before the sowin; season starts. Now, it is the time of showing for kharif crop. Therefore, is the Minister prepared to assure this House that the prices of agriculurai produce wouid be announced be ore the sowing season of the kharii crop? Secondly, is the Government prepared to assure this House that h deciding the prices, the peasants would be fully compensated in terms of the cost of production,, heavy increase in the prices of fertilisers, diesel md other vital agricultural inputs < nd the cost of the daily necessities >f life? Thirdly, is the Minister prepared to assure the House whether the Government will establish parity between the prices of industrial produces and agricultural produce? Finally Sir, is the Minister prepared to give an assurance that there will not be any rise in the issue prices of foodgra as?

RAO BIRENDRA SINGH; Sir,, the hon. Member has raised certain questions. On the one hand, he wants higher prices to >e given to the farmers; but knowinj very well the financial constraints, he is opposed to raising the issue prices, tie wants the people I to be fed cheapen at Government expense and ne does not want the farmers also to be given higher prices by i trying to reduce he subsidy that the I Government of In iia gives on issue of foodgrains in the public distribution system. .The p inciple of parity is in the view of the Government. But ag I have stated e irlier, this cannot be achieved completely because of certain reasons which the hon. Members know very well. It is very difficult to keep the prices to be paid to the farmers for their produce in the agricultural sector at the same level as the prices of industrial products or the finished goods for which agricultural produce is the raw material. But, as I have said, we try to achieve parity to the extent possible and it is for the first time this year that the Agricultural Prices Commission has been directed to keep the terms of trade between the two sectors in view and to take them into account while recommending prices for farmers' produce. He has asked that the minimum support prices should be announced before the sowing season. We try to announce the prices every year before the harvesting season. Even now we want to announce the prices for kharif season paddy before the harvesting time that will be in October or November, I cannot assure the House that it will always be before the sowing season that we will announce the prices. There are certain other implications. We do not want that the pattern of cultivation should be upset in the country because of the prices being remunerative for one produce and thereby reducing the cultivation of some other item of foodgrain or cash crop. Therefore, we want to have some sort of a stability in agricultural production in the various fields. Fir, as far as possible, the hon. Member's suggestion shall be kept in view. As I have already said,, he has very vehemently opposed the raising of issue price. But if the issue p.rice is not raised, the capacity of the Government to give higher prices to the farmer for his produce also is limited. Therefore, we cannot be the friend of both the farmers and the .consumers at the same time.

*SHRI JAHARLAL BANERJEE (West Bengal): Mr. Vice-Chairman Sir, from the reports appearing in

♦English translation of th8 original speech delivered in Bengali.

[Shri Jaharlal Banerjee]

yesterday's news papers w_e find that the Chief Minister of West Bengal has supported the price fixed by the Agricultural Prices Commission for paddy although Chief Minister of other States have asked for more. Sir, I am well aware of the fact that if the procurement price of paddy goes up then naturally it would mean some hardship for those who will buy rice. But it would be wholly wrong to ssume that all those who are engaged in the cultivation of paddy are all rich people or big Zamindars.

Mr. Vice-Chairman Sir,, you are no doubt aware of the fact that more than 50 per cent of the paddy cultivators own small pieces of land which vary between 2—5 acres and a disguised unemployment of an acute order prevails among them. Among these cultivators, the family has very often to depend on the earnings of one man and the person concerned has to arrange for food, cloth, medicines etc., in fact everything for the whole family out of his own income. I am mentioning this only to emphasise the fact that all these factors should be kept in yiew before the price of paddy is fixed. Sir, in West Bengal because of non-availability of electricity the power pumps that were installed at different places have gone out of order. As a result of this,, the cultivators have to put in more physical labour to fetch water to carry on their agricultural activities and this has resulted in an increase in their expenditure. Along with this, the price of buffalo, cow, etc. which are used by the cultivators has gone up very high. Even the fodder cost has reached a prohibitive point and it has become almost impossible for the cultivators to give oil cakes to their cattle which is their favourite food. Without the oil cakes, the nutritive value of the cattle feed has gone down aiid they can be utilised for at the most for one to two seasons only. The tale of woe of the farmers does not end here. He does not get manure in time or in sufficient quantity. Thu_s he is compelled to buy fertilizer in black market much against his own wishes. The agricultural farms do not supply them the good variety of seeds. Thus we rind that the cost of all agricultural inputs has gone up and therefore, I would demand that $_a$ higher procurement price should be given to the paddy growers. When we look around, we find that sugar is selling for Rs. 3 per Kg. and mustard Oil fo_r Rs. 12 per Kg. *(Interruption)*... After the days work when farmer comes back home, he cannot use a lamp to dispel the darkness of the rooms because he has no kerosene with him. Sir if you go through the daily newspapers of West Bengal, you will find that the rate of deaths because of snake bite is increasing yea_r after year. I would, therefore,, like to put a few questions to the Home Minister. I am not averse to the price of paddy being fixed at Rs 100/- or less,, but would the Hon. Minister please ensure that manure is supplied to the cultivators in time and in sufficient quantity?

My second question is that thp price of pesticide, which is used in sufficient quantity by those who are engaged in modern methods of paddy cultivation, has gone sky-high and I would like to know from the Hon. Minister as to what he proposes to do in this matter to give some relief to the cultivators.

Thirdly whether government would $conside_r$ to give subsidy and bring down the price of oil cakes which i? the favourite food for cattle in West Bengal.

Fourthly, Sir,, the government is not able to keep under control the prices of sugar and edible oil and we find that because of shortage of diesel, the agricultural pumps are lying idle.

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI SITA RAM KESRI): Sir, I want to .. .

SHRI JAHARLAL BANERJEE: I do not want any interruptions. I want to put my questions.

SHRI SITA Ri..M KESRI: Hon'ble Member, I am no interrupting you.

SHRI JAHARLAL BANERJEE: I want to ask que.'tion from the Minister.

SHRI SITA RvM KESRI: Hon'ble Member, I am n it interrupting you,, please rest assure 1. I am only request, ing the Chair ths t it was decided that Calling Attention and Special'Mentions will be finished ty 1.30 P.M. I am only reminding the Ciair of this position. It was also de< ided that the main speaker on the Calling Attention will speak some tl ings and the other hon'ble Members will put only questions taking three minutes each. I want to remind the Chair that if we do not abide by this decision...

THE VICE-< CHAIRMAN (SHRI SAWAISINGH S SODIA): Please conclude, Mr. Banei.ee.

*SHRI JAH/ RLAL BANERJEE: Sir, I would request the Hon'ble Minister to ensure thai items of daily needs are supplied at controlled rale or at a reasonable price to the poor cultivators who own laid between 5 and 20 acres. I would ike to know whether he would take some steps in this direction or not. Sir, we find that the government enhances dearness allowances for the g ivernment employees but the poor cultivators have no union, through which hey can voice their demands or grievances. On behalf of such poor cultivators, I appeal to the government to consider the suggestions that I have mad, and with this I conclude my speech, Sir.

RAO BIRENDRA SINGH: Sir, most of the questions raised by the hon'ble Member, Mr. Banerj'ee, have been already replied bj me. He has talked about certain ma'.ters which are. to my mind not relate! to the Calling Attention Notice. H *i* has pleaded the case of small farmers and he has asked for a higher price fo - paddy. I would like to inform him that only yesterday the

♦English translation of the original .speech in Benga i.

Chief Minister of West Bengal supported the recommendation...

SHRI BHUPESH GUPTA (West Bengal): He is not here. He is in Moscow.

RAO BIRENDRA SINGH: I am sorry, it was Food Minister, Mr. Sudin Kumar, certainly speaking on behalf of the West Bengal Government. He was not in favour of any rise in the minimum support price of paddy. According to him Rs. 100 was enough. Of course, there are two opinions against the States. The paddy producers want higher prices. Those which are largely consuming States and want food-grains supplied to them at subsidised rates, do not want that the issue price should be raised or evert that the price for the farmer' produce should be raised. So, we have to strike a balance and find a mean so that both sides are looked after. We shall see what can be done in this respect

He asked me to assure the House that pesticides, secticides and fertilisers will be supplied in time. We are making arrangements for these things to be supplied in time. Plant protection measures will also be speeded up. Certain imports also are being ordered in the case of pesticides which are not available in the country. Fertilisers also have been made available to all the States almost to the extent that We could distribute out existing stocks. But we also are waiting for imported fertilisers and it will be distributed as soon as we can clear it from our ports and as the ships arrive. I assure the hon. Member that we are fully aware of this problem.

Sir, he has raised certain other issues like prices of oil-cakes, fodder and raised even the issue of daily allowance and supply of daily needs. They do not come under the purview of thig Calling Attention motion and 1 do not think I should take the time of the House to reply to those points. But the sugar price which he said, is ruling very high. I am sure he knows that the price of sugar which is high in the

[Rao Birendra Singh]

free market i_s only in respect of free sugar. That is left to the factories to sell. The price of levy sugar has been kept very low. It is Rs. 2.85 per Kg... *(Interruptions).* I think, the hon'ble $Member_s$ will appreciate that sugar is being controlled. The ^{ver}y ^{lact} that 65 per cent of the sugar is taken from the producers to be supplied to the consumers at a very cheap rate of Rs. 2.85,. means that we are keeping the sugar prices down .. *(Interruptions)'.*

श्री हुक्मदेव नारायण यादव : अमीरों के लिए 2.85 पैसे प्रति किलोग्राम और गरीबों के लिए आठ रुपये किलो . . . *(Interruptions).*

RAO BIRENDRA SINGH: It ia meant for the entire population. In fact this high price in the market which is around Rs. 8/- now should not affect the poor people. It is only meant particularly fo_r the richer people or the people who are **very** fond of sweets. For the common man, khandsari gur i_s generally the item of consumption. But now the sugar that we are supplying under the distribution system is much cheaper than even the gur price at present. Therefore, we are trying to meet the requirements of the common man to the best possible extent that we can do.

I think, Sir, there is nothing else for me to reply. I thank the hon'ble Members.

REFERENCE TO THE REPORTED INFLOW OF FOREIGN FUNDS TO NORTH EASTERN REGION OF THE COUNTRY

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SAWAISINGH SISODIA): Now, we take up special mention by Shri Bhu-pesh Gupta.

SHRI BHUPESH GUPTA (West Bengal): Sir, I am glad that afier a long time I am getting a chance. Foreign money is pouring in from different countries in the West to north-eastern region. Sir, some time ago, I mentioned this thing in this House. I think it wa_s on the 9th of July when same mention was made. Since then, we have got more information about it. It appears from very reliable sources—well, I know from very reliable sources—that between October 1979 and March 1980, Rs. 39,04,226 were received from abroad from the Catholic Church and the money was received by the State Bank of India in Shillong. This amount came to a particular account, operated by Father Rubi in the name of his mission. Now, i would give you a little more details. On 9th October, 1979, Father Rubi—this is his name—withdrew, in the first instalment, 9,69,000 dollars. O_n 15th October, his withdrawal was 2,39,113 dollars. Then, on the 14th January, Rubi withdrew money equivalent of 2,86,944 pound sterling. Then, on the 18th January, he again withdrew money equivalent of 3,63,098 dollars. Next day, on 19th January, "he withdrew money equivalent of another 15,688 dollars. You can understand how much money is coming. On 31st January, his withdrawal was money equivalent of 79,798 dollars. I am mentioning these things because you should enquire. On the 27th February, money equivalent of 2,22,940 dollars wa_s withdrawn. As per the latest information I have, on the 29th February, again, money equivalent of 4,82,680 Swiss Francs was withdrawn. Now, Sir, money is coming from various Western countries into this disturbed region, where there is turmoil. Money is earning not only for the Catholic Church but for other sources also. These are only known figures. The Federal Bank has opened a branch in Shillong. As you know, this is a non-official private bank. They have opened a branch to facilitate this. I bring these things to your notice. I have brought these things to the notice of t'he Prime Minister also. These things should be taken seriously. Nothing is being done. Huge amounts are coming.